

>

**Title:** Discussion on the motion of thanks on the President's Address moved by Shrimati Sushma Swaraj and seconded by Shri Ajit Kumar Panja.

14.10 hrs.

MR. CHAIRMAN : Now, we will take up Motion of Thanks on the President's Address. The time allotted is eight hours.

Shrimati Sushma Swaraj may move the Motion.

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने २२ फरवरी, १९९९ को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’

सभापति महोदय, भारत के संविधान की धारा ८७ की उपधारा १ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जब भी नई लोक सभा गठित होगी, उसके प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक वर्ष संसद के होने वाले प्रथम सत्र के आरम्भ में राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करेंगे। उसी धारा की उपधारा २ में यह भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के अंदर उठाए गए मुद्दों पर संसद सदस्य चर्चा कर सकेंगे। उसी उपधारा के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत मैं आज महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इस चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ।

सभापति जी, हालांकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केन्द्रीय सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज होता है। लेकिन इसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पढ़ा जाना पूरे समारोह को एक भव्यता प्रदान करता है, एक गरिमा प्रदान करता है। लेकिन दुख की बात है कि इस तरह के गरिमामय समारोह में कभी-कभी गरिमा को भंग किए जाने की कोशिश की जाती है। मुझे दुख है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति जी के खड़े होने से पहले ही हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने अपनी बात उनके सामने रखनी चाही। मैं उस घटना को तूल न देते हुए उस संदर्भ में केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि हम कुछ अवसरों पर राजनीति करना छोड़ दें तो अच्छा होगा। इससे हमारी अपनी प्रतिष्ठा भी बचेगी और संसद की गरिमा भी। इससे राष्ट्रपति जी का सम्मान भी होगा और एक अच्छी संसदीय परम्परा का निर्वाह भी हम कर सकेंगे। मुझे लगता है कि मेरे सांसद साथी मेरी इस सलाह पर जरूर ध्यान देंगे।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ वह सरकार की सफलताओं का ब्यौरा देता है और दूसरी तरफ वह सरकार के आगामी कार्यक्रमों का खुलासा करता है। लेकिन क्योंकि इस बार यह अभिभाषण इस सदी का अंतिम अभिभाषण था इसलिए राष्ट्रपति जी ने स्वतंत्रता के बाद की तमाम उपलब्धियों पर गर्व करते हुए हमारे सामने खड़ी भावी चुनौतियों का सामना दृढ़ता और आत्मविश्वास से करने की सलाह हमें दी। यह भी सुखद संयोग था कि गणतंत्र की ५० वीं वर्षगांठ इस साल से शुरू हो रही है। इसलिए उन्होंने हमारी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया। मैं विशेषरूप से राष्ट्रपति जी की इन प्रारम्भिक बातों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ।

राष्ट्रपति जी ने अपनी बात राष्ट्रीय एजेंडा से प्रारम्भ की। राष्ट्रीय एजेंडा वह दस्तावेज है जिसे हमारी सरकार ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर शासन की नीति और कार्यक्रमों के रूप में स्वीकार किया है। मैंने पिछले दिनों इस सदन में हुए लगभग हर विषय की बहस को बहुत ध्यान से सुना है। इस समय मोहन सिंह जी सदन में नहीं हैं। मुझे याद है गोवा में राष्ट्रपति शासन पर अपनी चर्चा प्रारम्भ करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोगों को तो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को भूलने में ४० वर्ष लगे, लेकिन भा.ज.पा. वाले तो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को एक ही वर्ष में भूल गए। मुझे उस दिन ही यह बात अखरी थी, क्योंकि यह बात सत्य से परे है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ इस सदन को, कि यह सरकार केवल भा.ज.पा. की सरकार नहीं है, यह सरकार सहयोगी दलों के साथ चल रहे भा.ज.पा. नेतृत्व की सरकार है।

महोदय, मुझे कतई यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि हमारी बहुत सी राजनैतिक प्रतिबद्धताएं हमारे सहयोगी दलों के साथियों को मान्य नहीं हैं। इसलिए उनके साथ बैठ कर एक सर्व स्वीकृत कार्यक्रम के तौर पर हमने राष्ट्रीय एजेंडा स्वीकार किया है। वे जानते हैं कि यह वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों का तकाजा है जिसे स्वीकार करके हम चल रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय एजेंडा का ताल्लुक है, शायद ही केन्द्र में आज से पहले कोई ऐसी सरकार रही हो जिसने अपने घोषित कार्यक्रमों के इतने ज्यादा बिन्दुओं पर इतनी जल्दी अमल करके दिखाया हो, जितनी जल्दी इस सरकार ने राष्ट्रीय एजेंडे के बिन्दुओं पर अमल करके दिखाया है। हमारी पहली प्रतिबद्धता राष्ट्रीय सुरक्षा थी और मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण वहीं से शुरू किया। पैरा चार में उन्होंने कहा कि ‘गतवर्ष पोकरण में ११ तथा १३ मई को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम रहा है, जिससे भारत एक परमाणु सम्पन्न राष्ट्र बन गया है। सरकार ने यह कदम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद उठाया है।’ ११ मई का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। इस दिन प्रत्येक भारतीय ने जाती, धर्म और भाषा से ऊपर उठ कर केवल एक भारतवासी के नाते गर्व का अनुभव किया था। इस दिन राष्ट्रीय स्वाभिमान हूँकार उठा था, हर भारतीय सीना तान कर और मस्तक उठा कर चल रहा था।

महोदय, यह सही है कि पोखरण परीक्षण एक दिन में नहीं हुआ है। इसकी तैयारी हमारे आने के बाद शुरू नहीं हुई। यह सच है कि अनुसंधान पहले से चल रहे थे, यह सच है कि परीक्षण क्षमता पुरानी सरकारों के दौरान जुटाई जा चुकी थी लेकिन यह भी सच है सभापति जी कि क्षमता के बावजूद परीक्षण करने की अनुमति देने का साहस इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं जुटा पाए थे, केवल एक प्रधानमंत्री अनुमति देने का साहस जुटा पाए, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी।

उन्होंने एक तरफ अनुमति देकर अपने आत्मबल का परिचय दिया और दूसरी तरफ परीक्षण की सफलता के बाद दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करके विश्व के सामने अपनी स्टेटसमेंटशिप का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। मुझे खुशी है कि इन दोनों घोषणाओं का जिक्र राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया। पहली घोषणा यह थी कि भारत किसी गैर परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र के विरुद्ध अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करेगा। यह घोषणा भारतीय संस्कृति के उसी युद्ध धर्म के नियमों के मुताबिक है जिसके अनुसार कोई शस्त्रधारी योद्धा निहत्थे पर वार नहीं करता। वह या तो उसके हाथ में भी शस्त्र थमाता है या अपना हथियार फेंक कर लड़ता है। दूसरी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने यह की कि परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों के विरुद्ध भी इसके प्रयोग में भारत पहल नहीं करेगा यानि, नो फर्स्ट यूज़, नो ओफेंसिव यूज़, शायद इससे ज्यादा तर्कसंगत और युक्तिसंगत नीति परमाणु शस्त्रों के संबंध में नहीं हो सकती। निरस्त्रीकरण की बात पहले की सरकारें भी नहीं करती थीं। वे वैज्ञानिकों से अनुसंधान करवाती जाती थीं लेकिन जब परीक्षण की बात आती थी तो कहती थीं कि विकल्प खुला हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उस नीति का क्या औचित्य था कि हमने विकल्प खुला रखा हुआ है। हम दोनों तरफ दुविधा में थे। अंतरराष्ट्रीय जगत में हमारी आलोचना तब भी हुआ करती थी लेकिन अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा का विश्वास हम नहीं दिला पा रहे थे। एक कहावत है- 'दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम,' वही हालत हमारी हो रही थी। आज यह कह कर कि हम प्रयोग में पहल नहीं करेंगे, हम किसी दुविधा में नहीं हैं। यह कह कर कि हम वार पहले नहीं करेंगे, आज हमारी बात में वजन दिखता है, उसका अर्थ निकलता है। कुरुक्षेत्र की काव्य रचना में राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा था 'क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो' शक्ति जुटाए बिना शांति की बात करना कायरता लगता है लेकिन शक्ति सम्पन्न होने के बाद वार में, प्रयोग में पहल न करना शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, निष्ठा को दर्शाता है।

इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि परमाणु परीक्षण का फैसला इस सरकार ने अति-उत्साह में नहीं लिया था, यह फैसला महत्वाकांक्षी होकर भी नहीं लिया था। यह फैसला उतावली में भी नहीं लिया था बल्कि परमाणु परीक्षण का फैसला इस सरकार ने पूरे विवेक से, पूरे धैर्य से, पूरी दूरदर्शिता से लिया था। सभापति जी, क्योंकि राष्ट्रपति जी घटनाओं का सिलसिलेवार उल्लेख कर रहे थे इसलिए उन्होंने प्रारम्भ में पोखरण का जिक्र किया और लगभग अंत में प्रधान मंत्री जी की लाहौर यात्रा का उल्लेख किया। लेकिन मैं दोनों घटनाओं को एकसाथ जोड़कर सदन में रखना चाहूंगी। मेरा यह निश्चित रूप से मानना है कि यदि ११ मई १९९८ नहीं घटता तो २० फरवरी १९९९ भी नहीं घट सकता था। इन दोनों का आपस में सीधा रिश्ता है। भारत में घटा ११ मई का पोखरण और २८ मई को घटा हुआ पाकिस्तान का चगाई, उसी ने २० फरवरी १९९९ को संभव कराया था। क्योंकि दोनों देशों के बीच चल रही तारीखी मुकाबलों की होड़ मिट गयी। दोनों मुल्कों के खून में खौलती हुई प्रतिरोध की भावना शांत हो गयी और उसने पैदा किया दोस्ती के जज्बे को उसने खुली बाहों न्यौता दिया मित्रता को, उसने बस में चढ़ा दिया अटल बिहारी वाजपेयी को और उसने गले लगा दिया दोनों मुल्कों के प्रधान मंत्रियों को। वह क्षण एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे न हिंदी का भाव-विभोर शब्द अभि व्यक्त कर सकता है न अंग्रेजी का नौस्टैलजिया। वह एक ऐसा क्षण था, जिसके एहसास को शब्दों में बांधना मुश्किल है। वह क्षण केवल कैमरे में कैद नहीं हुआ था वह क्षण भारत और पाकिस्तान के अलावा विश्व की करोड़ों आंखों ने जो टकटकी लगाए उसे देख रही थीं, उसे कैद कर लिया था। उस पल ने पहल की है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाने की, उस घटना ने उम्मीद जगाई है वर्षों से लम्बित पड़े विवादों के समाधान की। इस तरह भारत-पाक मैत्री और परमाणु परीक्षण के दो खूबसूरत हाशियों के बीच, दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीच पड़ा गया राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसमें इस सरकार की बाकी सफलताओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा दर्ज है। उपसभापति जी, जब परमाणु परीक्षण हो गया तो उसके बाद कई बौखलाए देशों ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात की। मुझे खुशी है कि परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बिंदु को लिया और बहुत दृढ़ता से उसका सामना करने की बात की। भारत सरकार ने ऐसे समय में अपने प्रवासी भाइयों को याद किया। वित्त मंत्री ने एक योजना बनाई 'रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड'। जिसमें भामाशाह बनकर अनिवासी भारतीय सामने आए और उन्होंने सरकार का हाथ थामा। यह योजना जिसका कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था, तय नहीं किया गया था कि कितनी राशि रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड से आयेगी, लेकिन एक अंदाजा अर्थशास्त्री लगा रहे थे कि यदि दो बिलियन डालर यानी लगभग आठ-नौ हजार करोड़ रुपया रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड के माध्यम से देश को मिल जाए तो स्थिति में कुछ सुधार आ सकेगा। लेकिन आज मुझे यह बताते हुए गर्व है कि केवल तीन हफ्ते चली योजना, केवल १४ वकिंग डेज के लिए खुली हुई यह योजना भारत सरकार को कितनी धनराशि दे गयी। सफलता के आकलन से दोगुना ज्यादा। दो बिलियन डालर सफलता का लक्ष्य था लेकिन ४.२ बिलियन डालर यानी १८ हजार करोड़ रुपया रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड के माध्यम से अनिवासी भारतीयों ने भारत सरकार को सौंप दिया।

सभापति जी, मुझे याद आ रहा है पिछले हफ्ते यहीं एक पूरक प्रश्न पूछते हुए देश के पूर्व वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने एक सवाल पूछा था कि रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड की प्रूडेंस क्या थी? रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड के पीछे कौनसा विवेक काम कर रहा था और इसका क्या औचित्य था? मुझे खिन्नता का अनुभव हुआ था और मुझे हैरत भी हुई थी वह प्रश्न सुनकर। क्योंकि देश के पूर्व वित्त मंत्री के नाते उन्हें यह चीज मालूम होगी। वह पहले वित्त व्यवस्था यहाँ की देख चुके थे, वह जानते थे आर्थिक प्रतिबंधों के चलते भारत की आर्थिक भुगतान की स्थिति गड़बड़ा सकती थी। वे जानते थे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमें डाउन-ग्रेड किया हुआ था। अगर आज चिदम्बरम जी यहाँ बैठे हुए होते तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती कि संकट के समय अपनों का आह्वान करना क्या अविवेकपूर्ण निर्णय होता है, क्या इस तरह के निर्णय का तर्क भी हमें समझाना पड़ेगा। क्या उसकी प्रूडेंस हमें बतानी पड़ेगी? क्या उसके औचित्य का खुलासा करना पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहती हूँ कि जिस समय सारे ताकतवर मुल्क हिन्दुस्तान को आंखें दिखा रहे थे, जिस समय हम पर अनावश्यक दबाव बना रहे थे, उस समय भी यह देश अपनी रीढ़ की हड्डी तान कर खड़ा रहे केवल यही प्रूडेंस थी रीसरजेंट इंडिया बॉण्ड्स को जारी करने की, यही विवेक था उस योजना को शुरू करने का और यही औचित्य था उस फैसले का। हमने जब-जब स्वदेशी की बात कही तब-तब अनिवासी भारतीय को भारत का अंग मान कर कही। हमने स्वदेशी का खुलासा करते हुए कहा था कि भारत भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा लेकिन उस समय जब गांव में बसने वाले भारतीय की हमने कल्पना की थी उसी तरह अनिवासी भारतीय की भी कल्पना की थी। मुझे खुशी है कि हमारी जिस अपेक्षा पर अनिवासी भारतीय खरे उतरे, उस बात को आगे बढ़ाते हुए इस मिट्टी से उनका सम्बन्ध जोड़ते हुए हमने दो और बड़ी योजनाएं चलायी हैं - एक पी.आई.ओ. कार्ड की योजना। इसका मतलब है पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के नागरिक। हमने तय किया है कि भारतीय मूल के नागरिक अब भारत में वीसा मुक्त प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का खुलासा बहुत जल्दी गृह मंत्री करने जा रहे हैं। अब यहाँ भारतीय मूल के नागरिकों को वीसा की असुविधा आगे सहनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह की एक योजना का खुलासा इस बार के बजट में किया गया। उसमें कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों द्वारा लगाया गया १०० फीसदी धन और इनवैस्टमेंट को ऑटोमैटिक एप्रुवल मिलेगी। मैं इन योजनाओं का खुलासा इसलिए कर रही हूँ कि इन योजनाओं के चलते आज भारत के हजारों मील दूर रहने वाले उन अनिवासी भारतीयों को भारत की मिट्टी ज्यादा अपनी, ज्यादा करीब और ज्यादा सुगन्धित लग रही है।

सभापति जी, हमें और आपको विदेशों में जाने का मौका मिलता है। हमें लगता है कि वहाँ बैठे भारतीय एक सपना संजोए बैठे हैं कि वहाँ से कमाए धन को किसी तरह देश में लगाने का काम हो। मुझे लगता है कि अब उनका वह सपना साकार होने का वक्त बहुत नजदीक आ रहा है।

हमारी एक और प्रतिबद्धता थी पारदर्शी और ईमानदार शासन देने की। मुझे आज यह कहते खुशी है कि उस प्रतिबद्धता में पहल करते हुए हमारी सरकार ने लोकपाल विधेयक इस सदन में पिछले सत्र में प्रस्तुत किया। वर्षों से इस पर चर्चा चल रही थी और वह तरह-तरह की कमेटियों में भटक रहा था, हमने उसको ज्यॉट कमेटी के माध्यम से लाकर प्रस्तुत किया। केवल प्रस्तुत नहीं किया, वर्षों से देश में एक बहस चल रही थी कि प्रधान मंत्री को उसके घेरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए? यहां प्रधान मंत्री ने स्वयं सदन में खड़े होकर कहा कि इसकी परिधि में प्रधान मंत्री आने चाहिए क्योंकि वह किसी कानून से ऊपर नहीं है। जो लोकपाल बिल हमने प्रस्तुत किया प्रधान मंत्री उसके घेरे में लाए गए हैं। केवल यही नहीं सूचना के अधिकार की बात हुई। इस संबंध में हमने एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सूचना के अधिकार को लाने की प्रतिबद्धता केवल सदन के बाहर और सदन के फर्श पर खड़े होकर नहीं कही बल्कि राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा ४४ में उस प्रतिबद्धता को दोहराया। इससे पता चलता है कि हमारी निष्ठा सूचना का अधिकार देने के प्रति कितनी है? केवल यही नहीं इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने बहुत क्रांतिकारी पहल की। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी की ११ स्लैब को घटा कर ३ पर ला दिया। कस्टम ड्यूटी की ७ स्लैब को घटा कर ५ पर ला दिया। शायद आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस बात की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रणाली को प्रारम्भ करके उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार किया है। उन्होंने बजट बनाते समय बड़े व्यावसायिक घरानों की भूमिका को केवल इस बार नहीं बल्कि सदा-सदा के लिए समाप्त कर दिया। इसी तरह की एक ईमानदार पहल भारत के पर्यावरण मंत्री ने की। आप सब को वह पत्र मिला होगा। मुझे भी वह पत्र मिला जिस में उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई हर योजना को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया गया है। आजकल पर्यावरण काफी डेलिगेट मसला बना हुआ है। जब कोई योजना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत होती है तो बहुत सी भौहें उठती हैं। उसमें केवल योजनाओं का ब्योरा और नाम नहीं, किस आधार पर उन योजनाओं को मंजूरी मिली है, उन्होंने इसका पूरा विवरण इंटरनेट में डाल दिया।

सभापति जी, मुझे अपेक्षा यह थी कि विपक्ष के साथी सरकार के इन ईमानदार प्रयासों की सराहना करेंगे लेकिन मुझे दुख हुआ जब हमारी सरकार पर विपक्ष के कुछ साथियों ने भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ने चाहे। जोगी जी यहां नहीं हैं। उस दिन बहुत ऊंचे स्वर में कह रहे थे कि पांच हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अगर वह आज यहां होते तो मैं उनसे पूछती कि क्या उनका घोटालों का हेंग-ओवर अभी खत्म नहीं हुआ? खत्म कैसे होता? अभी पिछले हफ्ते इसी सदन में फर्जी वोट घोटाला घटा है। उस घोटाले से बाहर वह कैसे आते? मुझे जोगी जी से कोई नाराजगी नहीं है। मुझे इस बात का दुख हुआ कि इस बात को शिव शंकर जी ने उठाया। शरद जी बैठे हैं।

अगर शिवशंकर जी यहां बैठे होते तो मैं उनसे मुखातिब होकर यह बात कहती। वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। मुझे दुख इसलिये हुआ कि उन्होंने खुद झूठे आरोपों की पीड़ा भोगी है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ज़हर को खुद पिया है और उन्होंने खुद इस तरह के आरोपों की महंगी कीमत चुकाई है। मुझे इस बात का दुख है कि जो आरोप राई बराबर सच नहीं पाये गये उनके कारण उन्हें राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसलिये मुझे लग रहा था कि जो व्यक्ति इस तरह का भुक्तभोगी है, वह दूसरों पर आरोप लगाते समय थोड़ा संयम जरूर बरतेगा लेकिन उन्होंने संयम नहीं बरता। एक लेख के हवाले से उन्होंने हमारी सरकार पर बदनियती और बेईमानी के आरोप मढ़ दिये। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम में से कौन-कौन इस तरह के आरोपों का शिकार नहीं हुआ। क्या यह सच नहीं कि यह जानते हुये भी आरोपों में सच्चाई नहीं है, कई बार क्षुद्र स्वार्थों और हलकी राजनीति के चलते इस तरह के आरोप मढ़ दिये जाते हैं। शरद जी आपके पीछे बैठते हैं माधवराव, आपके बराबर मैं बैठते हैं मोती लाल जी वीरा और इधर मेरी तरफ बैठते हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री यशवंत सिन्हा, श्री मदन लाल खुराना। मेरी दाईं तरफ बैठते हैं श्री कल्पनाथ राय। उनके बगल में उस ब्लाक में बैठते हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ क्या कल्पनाथ जी के वे दिन उन्हें हम वापस लाकर दे सकते हैं जो इन्हें बेवजह जेल में गुजारे पड़े। क्या कोई मुआवज़ा तय करेगा उस पीड़ा का जो हमारे इन साथियों ने भोगी है? आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? पिछले दस सालों में इन बातों ने बहुत तूल पकड़ा है और बेवजह प्रोसीक्यूशन का सिलसिला चलता रहा है, उससे छोटे राजनैतिक लाभों की प्राप्ति शायद हो सकती है लेकिन देश को भारी कीमत इसके लिये चुकानी पड़ेगी।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): इसमें कमल नाथ जी का नाम भी होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अभी तो मैंने थोड़े से नाम प्रतीक स्वरूप लिये हैं लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन-कौन इसका शिकार नहीं हुआ। मैं शरद जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि पक्ष और विपक्ष की भूमिका तो बदलती रहेगी। कभी हम उधर तो कभी आप इधर मगर देश चलता रहे। छोटा राजनैतिक लाभ उठाने के लिये हम एक-दूसरे को भभकती भट्टी में न झोंकें जिसके कारण देश के लोगों की आस्था इन संस्थाओं में जलकर खाक हो जाये तथा पूरे देश के प्रतिनिधियों को लोग बेईमान सोचें। यदि उनका विश्वास उठ गया तो इसकी भारी कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ेगी। इसलिये मैं अपने साथियों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर मेरी सलाह पर ध्यान देंगे तो इस देश को इस भट्टी में झोंकने से बचा सकते हैं।

सभापति जी, हमारी सरकार ने इस राष्ट्र को समृद्धशाली राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा है। मुझे मालूम है कि यह स्वप्न तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक इस देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत मजबूत नहीं हो जाता। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने पैरा २१ और २८ में केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिये दिये गये वायदों को पूरा करने के लिये जो कदम उठाये हैं, उनका जिक्र किया है। मैं ऐसी सभी योजनाओं का जिक्र नहीं करना चाहती लेकिन एक उल्लेखनीय योजना रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना का जिक्र जरूर करूंगी। यह योजना सिल्वर से सौराष्ट्र और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ६-लेन वाले सड़क मार्ग से संबंधित है। यह एक्सप्रेस हाईवे निर्माण की योजना है। शायद आज कुछ लोगों को यह योजना महत्वाकांक्षी और अव्यवहारिक लग रही होगी लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जिस समय सड़क-आजमयाणी शेरशाह सूरी ने जी.टी. रोड के निर्माण की कल्पना की थी।

तो शायद उनके भी कुछ अमात्यों ने यह सोचा होगा। उनके कुछ लोगों ने भी उसको अव्यवहारिक योजना ही कहा होगा, उसको महत्वाकांक्षी योजना कहा होगा लेकिन आज उस सड़क पर हम सब गर्व करते हैं। आप जानते हैं कि इस देश के औद्योगिक विकास के लिए, रोड़ के विकास के लिए रेल के इन्फ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है और मैं इस सदन के फर्श पर खड़ी होकर कहना चाहती हूँ कि यह योजना न व्यावहारिक है और न महत्वाकांक्षी है। इस सरकार की इच्छाशक्ति का तकाजा है कि वह इस योजना को पूरा करके दिखायेगी और हिन्दुस्तान को एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत डेवलपड इन्फ्रास्ट्रक्चर सड़क का बनाकर देगी क्योंकि इस सरकार ने इच्छाशक्ति के बीसियों फैसले पहले ही कर डाले हैं, जो अपने आप में उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कावेरी जल विवाद के समाधान का जिक्र करना चाहूंगी। आप तो जानते हैं क्योंकि आप वर्षों से इस सदन में रहे हैं। आपने कावेरी विवाद को यहां पर उठाते हुए देखा होगा। दशकों से चला आ रहा यह विवाद कोर्ट कचहरी के बीच भटकता अदालतों और आयोगों के चक्कर काटता, बीसियों याचिकाओं के बीच फंसा बढ़ता ही चला जा रहा था, धंसता ही चला जा रहा था लेकिन राष्ट्रीय हित का नजरिया रखते हुए बिना स्वार्थ या बिना छोटी राजनीति पर निगाह रखे हुए सबको स्नेह और सम्मान देने की परि वार के मुखिया की जो भूमिका होती है, वह भूमिका निभाते हुए इस सरकार ने कावेरी जल विवाद का समाधान निकाल दिया, उसका हल निकालकर रख दिया।

इसी तरह मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दो फैसलों का जिम्मा करना चाहूंगी। जैसा मैंने कहा कि आप वर्षों से इस संसद में हैं। आपने देखा होगा कि फिल्म जगत से जुड़े हुए सांसद, चाहे बजट की चर्चा में भाग लेते थे चाहे आई.एंड.बी. मिनिस्ट्री की वकिंग की चर्चा लेते थे, हमेशा एक मांग उठाते थे। ४० सालों से निरंतर यह मांग इस सदन और उस सदन में चली आ रही थी कि फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया जाये। आज मुझे यह बताते हुए खुशी है कि जो काम पूर्व की सरकारें ४० वर्षों तक नहीं कर पाई, वह इस सरकार ने ४० दिन में कर दिया और पहला बजट प्रस्तुत करते हुए उस पर वित्त मंत्री ने सहमति की मोहर लगा दी।

... (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : कृषि के बारे में क्या किया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : जहां तक कृषि की मांग है इस बार का पूरा बजट कृषि पर आधारित आया है। राजेश जी, आपको मुखातिब करते हुए वित्त मंत्री जी ने उस समय कहा था। मैं भी उन योजनाओं का जिम्मा करूंगी लेकिन अभी मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उन दो अहम फैसलों का जिम्मा कर रही हूँ। ४० साल तक वह सरकारें जो ना कर सकीं, वह इस सरकार ने ४० दिन में किया। इसी तरह एक दूसरा फैसला भारतीय कम्पनियों को अपलिंकिंग देने का था। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे एक अताकिंक नीति इस देश में चल रही थी? भारत की कम्पनियां मास्को, थाईलैंड और सिंगापुर के आगे चक्कर काटती थीं, आर. बी.आई. के सामने हाथ बांधकर खड़ी रहा करती थीं।

14.38 hrs. (Shri Basudeb Acharya)

उनके अधिकारी शाटलिंग किया करते थे और वह कहते थे कि भारत में अपलिंकिंग की सुविधा मौजूद है तो क्यों नहीं देते? पता नहीं वह तर्क विहीन नीति इस देश में क्यों चल रही थी? इस सरकार ने एक नीति बनाई और उस नीति के चलते उन तमाम भारतीय कम्पनियों को जो मास्को, थाईलैंड और सिंगापुर से अपलिंकिंग की सुविधा ले रहे थीं, उनको यह सुविधा तीन महीने के अंदर उपलब्ध करा दी।

राजेश जी, अब जरा इधर तवज्जो दीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कृषि की योजना है। राजेश जी मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ। आपने किसान की बात कही, तो मैं कह रही थी कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, फसल बीमा योजना किसानों से ही संबंधित योजनाएं हैं। चीनी उद्योग के डी-लाइसेंसिंग की योजना और प्रति वर्ष २० लाख मकानों का निर्माण करने की इतनी बड़ी योजना यह सरकार लेकर आई। हमारे यहां कहते हैं कि अगर गृहिणी ने देखना हो कि चावल उबले हैं या नहीं तो वह पूरा पतीला नहीं देखती केवल एक कण निकालकर ही पता लगा लेती है कि पतीला गला है या नहीं। इसलिए मैं उन योजनाओं का जिम्मा कर रही हूँ, जो प्रतीक के तौर पर आपके सामने यह बात रख देंगी कि यह सरकार किस तरह की इच्छाशक्ति रखती है।

... (व्यवधान)

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): यूरिया के भाव का क्या हुआ? ... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप तमाम वर्षों से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं।

यदि इस बार के अभिभाषण में आपने एक बात औबजर्व की हो, पिछले कई वर्षों से महामहिम राष्ट्रपति जी कश्मीर की स्थिति पर केवल चिन्ता व्यक्त कर रहे थे लेकिन पहली बार राष्ट्रपति जी ने कश्मीर की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया है और शब्द कहा है, मैं संतुष्ट हूँ कि कश्मीर में स्थिति सुधर रही है। यह स्थिति केवल कहने के लिए नहीं सुधर रही बल्कि धरती पर सुधरी हुई दिखाई देती है।

किसी भी जगह की शांति और व्यवस्था को जांचने के लिए पर्यटन सबसे बड़ी कसौटी होती है। दसियों वर्षों से जो पर्यटन डूबा पड़ा था, दसियों वर्षों से कभी पर्यटक कश्मीर की तरफ मुंह नहीं करते थे, करें भी कैसे, जान हथेली पर रखकर कोई सैर-सपाटे के लिए नहीं जा सकता, आज उस कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगांव फिर से खिल गए हैं, आज उस कश्मीर के डल लेक के शिकारे फिर से आबाद हो गए हैं, आज उस कश्मीर में होटल्स की ऐडवांस बुकिंग चल रही है। आज से कुछ महीने पहले मैं रेडियो कश्मीर की पचासवीं वर्षगांठ के सिलसिले में श्रीनगर गई थी। मैंने वहां अपनी आंखों से जब सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों को पाकों में घूमते हुए देखा तो खुशी से मेरी आंखें नम हो गई थीं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि यह हमारे लिए केवल शांति का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हमारी कश्मीर की शांति की मंजिल वह होगी जिस दिन वहां से निकला हुआ विस्थापित कश्मीरी वापिस अपने घरों को लौट सकेगा और हम वह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहां से निकला हुआ कश्मीरी २० जनवरी को एक दिन मनाता है, उस दिन का नाम उसने 'होलो कास्ट डे' दिया है। यह वह दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन उन्हें देश निकाला मिला था। वे दिल्ली में भी उस समारोह का आयोजन करते हैं। इस २० जनवरी को मैं उनके इस समारोह में गई थी। वहां मैंने इस सरकार की प्रतिबद्धता उनके सामने रखी थी और कहा था कि आप आज होलो कास्ट डे मना रहे हैं, नौ साल पहले, २० जनवरी, १९९० को आपको देश निकाला मिला था लेकिन यह इस सरकार की प्रतिबद्धता है कि होलो कास्ट डे नहीं, आप 'रीयूनिन डे' मनाएं और वापिस कश्मीर में अपनी उस सम्पत्ति पर काबिज हों और शांति से रह सकें। वह हमारी मंजिल है लेकिन ये सुखद पड़ाव हमें उस मंजिल तक जरूर ले जाएगा, इस अभिभाषण से यह आशा बंधती है।

इसी तरह पूर्वोत्तर की बात है। पूर्वोत्तर में जहां तक शांति स्थापना का सवाल है, मुझे खुशी है कि यहां खड़े होकर देश के गृह मंत्री ने जब एन.एस.सी.एन. की टॉक्स के संबंध में बात रखी तो वक्तव्य देते हुए कहा था कि एक वर्ष का युद्ध विराम हुआ है। यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से पहले कभी दो महीने, कभी तीन महीने के युद्ध विराम हुए। तीन महीने के युद्ध विराम में आप स्थायी शांति की तरफ नहीं बढ़ सकते लेकिन पहली बार वहां के बागी संगठनों ने इस सरकार पर भरोसा व्यक्त किया, जब एक वर्ष का युद्ध विराम किया। और मैं इस संसद में खड़े होकर कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े युद्ध विराम के समय का उपयोग करके सरकार पूर्वोत्तर में स्थायी रूप से शांति स्थापित करने की तरफ बढ़ेगी और हम इस प्रतिबद्धता को पूरा करके दिखाएंगे। केवल यही नहीं, जहां



तक पूर्वोत्तर के विकास का संबंध है, मुझे खुशी है, वहां के लोग हमेशा उद्योग की मांग करते थे लेकिन इस बार के बजट में दस साल का टैक्स होलीडे पूर्वोत्तर के लिए दिया गया है। दस साल के टैक्स होलीडे का मतलब है कि पूर्वोत्तर में अपार औद्योगिक विकास होगा। इसके साथ ही कितनी बड़ी घटना घटी है, इस बार मणिपुर में इस सरकार ने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया। लाइव टैलीकास्ट हुआ, पहली बार पूर्वोत्तर का वह व्यक्ति भारत के आम हिस्से के साथ भावात्मक ढंग से जुड़ा और भारत के आम आदमी की एक भावात्मक एकता पूर्वोत्तर के साथ स्थापित हुई। सच तो यह है कि हर व्यक्ति, हर वर्ग, देश और विदेश के लोग इस सरकार में अपना भरोसा व्यक्त कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, लाखों पर्यटकों ने कश्मीर में होने वाली शांति पर अपने विश्वास की मोहर लगाई।

... (व्यवधान)

मैं भरोसे की बात कर रही हूँ, मैं विश्वास की बात कर रही हूँ, मैं कह रही थी कि लाखों पर्यटकों ने कश्मीर में पहुंचकर वहां पैदा हुई शांति पर अपने विश्वास की मोहर लगाई। रिसर्जेंट इंडिया बॉडस के माध्यम से पैसा देकर अनिवासी भारतीयों ने इस सरकार के साथ सहयोग की मोहर लगाई। मियां नवाज़ शरीफ ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्वागत करके भारत-पाक मैत्री के ऊपर मित्रता की मोहर लगाई। लेकिन मुझे मालूम है कि इस सरकार का चलना हमारे विपक्ष के साथियों को सूट नहीं करता, इसका बने रहना भी सूट नहीं करता इसलिए ये इस अभिभाषण पर सहमति की मोहर नहीं लगाएंगे।

मुझे अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहती हूँ। शरद जी, जब आप नेता विपक्ष के नाते इस अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हों तो इस सरकार का मूल्यांकन करते समय कम से कम एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इस सरकार को विरासत में क्या मिला था। जिस समय हमने सत्ता संभाली थी, हमें विरासत में मिली थी एक भ्रष्ट राजनैतिक व्यवस्था, हमें विरासत में मिली थी एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, हमें विरासत में मिली थी एक सुस्त और बोझिल प्रशासनिक व्यवस्था, और तिसपर पूर्ण बहुमत का अभाव। एक अल्पमती सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं, एक गठबंधन सरकार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन उन सीमाओं और दबावों के चलते हुए इस सरकार ने जो काम किये हैं, कुछ मोर्चों पर तो यह दिशासूचक सरकार के तौर पर याद की जायेगी। हमें भीष्म पितामह का वह वाक्य मालूम है, मुझे याद है, जिस समय शरशैय्या पर वे लेटे हुए थे और धर्मराज युधिष्ठिर उनसे राज्य संचालन की शिक्षा लेने गये थे तो भीष्म पितामह ने कहा था कि धर्मराज अतीत को कोसकर तुम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। अगर अतीत अच्छा होता तो तुम्हें शासन सौंपा ही क्यों जाता।

इसीलिए हम इस विरासत की ओट में या इन सीमाओं के चलते किसी तरह की जिम्मेदारी से बरी नहीं होना चाहते। हम इस व्यवस्था के तंत्र को झकझोर रहे हैं, हम यथास्थितिवाद से इस देश को उबारना चाहते हैं। इस देश को हम झकझोर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और उस दिशा में एक-एक कदम बढ़ा रहे हैं।

बहुत बार मुझे लेकर कुछ बात कह दी जाती है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, यह सरकार मेरी सरकार है, यह सरकार मेरी पार्टी की सरकार है, यह सरकार वर्षों के संघर्षों और परिश्रम के बाद बनी है। इस सरकार के बनने में लाखों लोगों की तपस्या और साधना लगी है। यह सरकार चले, अच्छी चले, यही बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यशस्वी हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, यही कामना करते हुए और प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए मैं यह धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूँ।

MR. CHAIRMAN : Shri Ajit Panja, may second the Motion.

SHRI RAJESH PILOT : Shri Panja's party will be out of the Parliament this Session. We have read in the newspapers that Trinamul Congress will boycott the Session till the telecom rates are not revised. Have they revoked their decision?

SHRI AJIT KUMAR PANJA (CALCUTTA NORTH-EAST): Sir, as usual Shri Pilot is not well informed. The telecom issue has been kept in abeyance and therefore, we are here. He should be properly informed having known his background and knowing me.

Sir, I am grateful to you for calling me to second the Motion of Thanks on the President's Address.

Sir, I second the Motion. The momentous Address has been accepted by the people with great acclaim because in a very lucid manner our President had delivered the speech, touching the very heart of the people. It is also memorable having its source from Article 87(1) of our Constitution on the 22nd of February our President delivered the speech to both the Houses of Parliament.

I must congratulate the Government for National Policy on Agriculture. Eighty per cent of population is living in the rural areas. The other day the Planning Commission stated that 78 per cent of our population is living in the rural areas. The hon. Members will please give their mind that all of them are in the private sector. Our kisans and tillers are not in the public sector. They have no commune. There is no such Soviet system in agriculture. But they are all with two bigha zamin and green revolution was brought during Indiraji's time in 1967. I know that CPI Members do not like it. In 1967, Indiraji brought green revolution. I congratulate them for at least doing something. The number of kisans who got credit has gone up to 20 lakh from six lakh. This is a commendable thing. We must find out something for them so that they can really utilise it. The kisans of our country are excellent. You give them water to drink and water for the purpose of cultivation, they will really bring in gold for our mother India. Therefore, watershed management has been created in one hundred priority districts. It is

really a commendable thing. I am sure that the Agriculture Minister will please see that these are implemented as quickly as possible.

Red revolution is good for our own country, whether it takes place in 1917 or 1950. In our country, the green revolution established history and this Government has established white revolution.

It was the highest milk production, 720 lakh tonnes, in the whole world in 1998-99, and it was one of the most befitting things done by this Government.

SHRI MULLAPALLY RAMACHANDRAN (CANNANORE): The achievement was made during the last one year! What are you talking about?

SHRI AJIT KUMAR PANJA : In the year 1998-99, the milk production has gone up to 720 lakh tonnes.

SHRI A.C. JOS (MUKUNDAPURAM): Do you know at what age a cow gives the milk?

SHRI AJIT KUMAR PANJA : What do you mean?

SHRI A.C. JOS : You understood my question, but you do not want to reply to me.

MR. CHAIRMAN: Shri Jos, he is not yielding, please take your seat.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : I know that my learned friend is still labouring under his previous symbol of 'cow and calf'. I know that he is still labouring under it.

India has produced 720 lakh tonnes of milk, and we have ushered into this 'white revolution' in the year 1998-99. I found from the records that India has become the world's largest milk producer. In regard to wheat production, India has obtained the third position in the whole world where wheat is being produced. These are the commendable things which this Government has been able to do.

About Kisan Credit, I have already discussed it earlier and placed my views before this House.

Coming to infrastructure, Sushmaji has already spoken about this particular road. Hon. Members, please do not think that it connects Silchar to Saurashtra or Jammu and Kashmir to Kanyakumari. We are also aware of the golden quadrangle connecting all our big cities. But kindly think of the movement that will take place. We are not realising that. This is a boon for the integrity of the country. The movement from Kashmir to Kanyakumari and from Silchar to Saurashtra with the connecting link to all the cities will express the diversity and the culture of India. It is not a lane only because this type of infrastructure will give expression to our cultural heritage. This Government has done a great thing by proposing a National Integrated Transport Policy, which means all the airports, ports, rivers and also units which will connect roads will come under this. It will not only help the economic development of our country but will also bind our different cultures together. This will further strengthen the unity in diversity.

So far as the working-class is concerned, I am happy to note that some attempts have been made and I find that a thought has been given for improving the lot of the working-class. I find that this Government is addressing itself to the problems of the unorganised labour. In case of organised labour, trade union movement has gained ground in our country. But in case of unorganised labour, they are in great difficulty. Being a lawyer myself, I had a free interface with this unorganised labour. They are strewn all over and there is no proper legislation. This Government has addressed itself to the problems of this sector, namely, social security, occupational health safety, minimum wages and safeguards. I had an occasion to deal with seven lakhs of permanent workers in the coalfield area. My personal experience is that not only their wages have to be increased, but we must also give them good homes.

Working class people should be given a sense of security of home. They must have a good house to live in. They should be able to feel that their wives and children are safe at their home while they are in their work place. This would improve their health which will in turn increase their productivity. I welcome the second National

Commission of Labour which has been set up after 30 years. This will go a long way in improving the lot of our working class.

If I do not mention the great work done by this Government for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it will not be proper. The fund allocation for these sections of people has been increased three times. I congratulate the Finance Minister and the Government on this. Fund allocation for the two most important corporations, the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance Corporation and the National Backward Classes Finance and Development Corporation, has increased three times. This will go a long way in improving their lives. I hope the hon. Members from the Congress party would realise that helping those who indulge in killing dalits will not take them anywhere but helping this Government to carry out this work will improve the lives of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and instill a feeling in them that they are not a neglected lot.

The Government must take care to see that certain malpractices are curbed. Files are put up for permission to release reserved vacancies into open category on the pretext of nonavailability of candidates in the reserved categories. This practice must be stopped. It must be looked into as to where the posts are advertised. I have personal experience in some of the Departments where I had the opportunity of working. Once a file was put up to me with the request that certain vacancies in the reserved category should be de-reserved as there was not availability of candidates in the category of Scheduled Castes and Scheduled Tribes even after the mandatory advertisement was issued. I asked for the advertisement and I found that a vacancy in Tripura was advertised in an English newspaper in Maharashtra. By doing this, they complied with the formality of advertisement and ultimately denied the job to the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This must be taken care of by this Government and the officers concerned. The right of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people as provided under the Constitution must be given to them based on the policy.

Sir, I must say a few words about our mothers. If our mothers are not properly looked after, if women are not properly looked after, we will be nowhere. The first facts of life we learned were sitting on the lap of our mothers. Our mothers are our first private tutors. I must congratulate this Government for giving mothers the prestige due to them. This Government must be congratulated for showing its concern and making a provision for giving 10 kg rice per month free of cost to a person who is old and living in a rural area. They may not be able to reach many places. But this Government must be congratulated for the love and attention that they have shown to our elders. In my village in Burdwan, old people came running to me and said, "Mr. Panja, our sons could not look after us but this Government thought of us. We saw in the newspapers that we will be getting 10 kg rice in a month free of cost. We are very happy." I suggest that this Government must implement it.

Hon. Minister is sitting here. I appeal to him to leave aside all matters and implement this programme. Wherever the Minister goes, he should find out from the Block Development Officers, who are the kingpins in our system in India, whether they have done a survey to find out the number of old people living in their areas and whether 10 kg rice is distributed to them free of cost. There are nearly 558 blocks. If this is done, we would be doing a great help to people. If this is done, I tell you that God will bless you; and Allah will give you dua.

I quite remember, when I was in the Planning Ministry, our beloved Prime Minister Rajiv Gandhi called me and told: "Mr. Panja, can you give me one fair price shop within one kilometre of the mother's home? Mr. Panja, can you give me one potable water point two kilometres from our rural mothers?"

And, this is the idea you have been able to carry out. I must congratulate you. Please go ahead and see that this is implemented thoroughly.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : I am concluding within a few minutes.

Sir, now, I come to the point of Education. We are at the end of this century. At the turn of this century, what Swamy Vivekananda has said about Education, and I quote:

"A nation is advanced in proportion as education and intelligence spread among the masses...If we are to rise again, we shall have to do it by spreading education among the masses. Educate and raise the masses, and thus alone, national revival is possible."

Now, we are at the end of this century. This Government must be congratulated for finding out what Swamy Vivekananda has said in their Budget Speech. I was astounded when I found that the hon. Finance Minister has made a provision that there will be one primary school within one kilometre of habitation. If he implements it, he will worship the Theory of Entitlement enunciated by Prof. Amartya Sen, by which he got the Noble price. Education right is the Theory of Entitlement. Please take it to the people. If he implements the purpose of having one primary school within one kilometre of a habitation, it will turn India around, and we will be able to have proper planning and development of India.

There is a saying:

स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।

It means that 'Kings and the Ministers are worshipped in their countries alone but a learned man is worshipped all over the world.'

There is also a saying:

उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम्।

It means that 'A man who is transparent and open in his mind, the whole world is his own place.'

Therefore, this education, this Theory of Entitlement, as enunciated by Prf. Amartya Sen has been given proper regard by this Government, and I am sure that they will implement it, and we will be able to go a long way.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Sir, I will just concluding.

MR. CHAIRMAN: Now, this should be your concluding point.

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Yes, Sir, this is my concluding part.

MR. CHAIRMAN: It should be your concluding point and not part.

... (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Sir, after the Pokhran Test was conducted, there was a lot of criticisms by them as if we are going to attack Pakistan. But after it was conducted on 11th and 13th May, 1998, within seven days, another country reacted thinking as if we are competing with them. No, this is not so. Otherwise, our Prime Minister would not have gone there by a public bus from Delhi to Pakistan. He went there with the goodwill which has supported the confidence building exercise. His Lahore visit has created a sense of confidence building between the two countries and the neighbouring places.... (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Do you want to say something? ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

... (Interruptions)

SHRI AJIT KUMAR PANJA : Sir, I do not blame them. After finding our Prime Minister going by bus to Lahore, some people in Bengal belonging to Marxist Communist Party and their leaders are thinking of going by Hero Bicycle from Calcutta to Dhaka. Let them do so. I do not blame them. They have missed the bus and now they are quarreling about it.

Sir, this has gone a long way in establishing what is required to be done. Therefore, in 12 months of this Government, I tell the House one by one the 12 things done by them, let alone many other things.

I would like to make the following observations about the achievements of this Government: -

(i) This Government proved that by taking care of regional aspirations National Agenda could be formed and the country could be run.

(ii) Pokhran successful nuclear tests have made India brave and strong.

(iii) The proxy war of terrorists has been controlled. The number of tourists has increased in Jammu & Kashmir.

1531 hour (Dr. Laxminarayan Pandey in the Chair.)



(iv) Secularism has been established firmly by maintaining peace and communal harmony and this Government has been able to prove that in one year, there has been minimum amount of bloodshed than in the last ten years due to communal violence. The best Puja and the best of the religious festivals could be continued this full one year long and not a single incident has taken place and wherever there was any incident, this Government immediately tackled it.

(v) Annual GDP growth rate targetted at 6.5 per cent with Indian rupee becoming stable despite technology restrictions by some interested countries. (vi) This Government have caused white revolution with expected milk production of 720 lakh tonnes and becoming the third largest milk producing country in the world.

(vii) Six National Integrated Highway Projects establishing National Integration firmly from Kashmir to Kanya Kumari and from Saurashtra to Silcher have been taken up.

(viii) Internet Service provider policy to accelerate the spread of Internet services in the country has been adopted. There is effective progress in software.

(ix) Housing and Habitat Policy, 1998 to facilitate additional 20 lakh houses in a year has been adopted and easy loans are provided for housing.

(x) Second National Commission on Labour after 30 years for all- round improvement of our working class has been set up.

(x ) Primary education is becoming widespread by establishing Prof. Amartya Sen's theory of entitlement i.e., one primary school within one kilometre of habitat.

(x ) Extreme good relationship with the neighbours, particularly Pakistan and improved foreign policy have been established.

With these words, I support the Motion of Thanks and second it.

Charaive Bati excelsior Vande Mataram Jai Hind. We must work and advance altogether leaving aside our political aspirations and political struggle.

(ends)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members present in the House whose amendments to the Motion of Thanks have been circulated may, if they desire to move their amendments, send their slips to the Table within 15 minutes indicating the serial number of the amendment they would like to move. Those amendments only will be treated as moved. A list showing the serial numbers of amendments treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 22nd February, 1999'."

श्री शरद पवार (बारामती): सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा जो अभिभाषण संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिया गया है, उस पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस समय भारत देश कठिन समय से गुजर रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे कठिन समय में श्री के.आर. नारायणन जैसे व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद की बागडोर सम्भाल रहे हैं, जो पूरे देश का बड़ी अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस मिलिनियम में शायद उनका संसद का आखिरी अभिभाषण हो सकता है। हम नई शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी कल्पना है कि जब नई शताब्दी में हम जाएंगे तो भारत विश्व में एक शक्ति बनकर महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरकर सामने आना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनना चाहिए। जहां प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र जीवनयापन करने का अधिकार हो। इसके साथ ही सभी की धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में मजबूत करने की परिस्थिति पैदा करना जरूरी है।

समय का तकाजा है कि भारत एक शक्ति के रूप में उभरे। इसमें कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार, और सृजन के क्षेत्र में समुचित आधार पाने की आवश्यकता है। औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रों में हुए विकास को भी इस देश को ग्रहण करना पड़ेगा, भारत को भी एक गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, जहां शिक्षित समाज हो तब उनके जीवन में एक विश्वास पैदा हो सकता है। मगर इस कल्पना को साकार करने के लिए यह आवश्यक है, जिस सरकार की सोच ऐसी हो जो इस देश को नयी शताब्दी में मजबूती से आगे ले जा सकती हो। हमारा दुर्भाग्य है कि समय के इस मोड़ पर आज केन्द्र सरकार में ऐसी सरकार है जिनका कार्यकाल दैनिक आधार पर है। इनके प्राण, १८ सहयोगी, इनके हाथ में हैं और वे अपनी-अपनी दिशा में खींचते हैं। कभी-कभी यह पता लगाना कठिन होता है कि इस सरकार की कुंजी दिल्ली में है, कलकत्ता में है या मद्रास में है। हमने देखा कि इस सदन में कल ही एक आपत्ति आई थी। टेलीकाम रेगुलेटरी आथोरिटी का निर्माण करने के बाद इन्होंने कुछ डिजीजन ले लिया और हम उस निर्णय के साथ पूरे नहीं थे। खास कर गांवों की टेलीफोन की परिस्थिति को देखने के बाद वहां और मदद की आवश्यकता थी। मगर एक आथोरिटी बनाई गई थी और वह बनने के बाद, उनके निर्णय लेने के बाद इसी सदन में हमने देखा कि ममता जी का रवैया क्या था। पावर टेरिफ की जो आथोरिटी कई स्टेटों में बनाई है इस पर भी कई राज्यों में वहां के लोग जिस तरह कदम उठाते हैं इससे पता लगता है कि जिस निर्णय के अमल के लिए आज देश में आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी इस बारे में बड़ी गंभीरता से बोलते हैं, इसको सहयोग देने के लिए इनके साथियों की तैयारी हमें आज दिखाई नहीं देती।

मगर इसमें एक-दो बातें हैं, जिनका मैं सरकार को इशारा करना चाहता हूँ। जिस दिन प्रधान मंत्री जी लाहौर गए, उनका एग्रीमेंट हुआ, तब वैली में कुछ शक्तियों ने कुछ लोगों की हत्या कर दी।

17.06 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम ईमानदारी से कदम उठाना चाहते हैं, अपने पड़ोसी देशों से, खासकर पाकिस्तान के साथ रिश्ते मधुर बनाने के लिए, तो ऐसे में कोई बाहरी शक्ति और अपने देश की साम्प्रदायिक शक्ति दोनों मिलकर उस कदम को विफल करने की कोशिश करेंगी, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा और सख्त नजर रखनी होगी। हमें यह कोशिश करनी होगी कि जो कुछ हम कदम उठाना चाहते हैं उससे दूर नहीं जाएं। वहां के वजीरे-आजम ने कुछ बयान दिए, वे कुछ अच्छे नहीं थे। हो सकता है अंदरूनी परिस्थिति के चलते उन्होंने दबाव के कारण ऐसा किया हो। यहां भी कुछ बयान हमने दिए, जिनको मैं ठीक नहीं मानता। पाकिस्तान से जो रिश्ते सुधारने की बात है, इस पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका लाभ भारत और पाकिस्तान दोनों को होगा। भारत की आंतरिक शक्ति को भी मजबूत करने के लिए, देश हित के लिए यह जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत किया है, यह कोई अलग बात नहीं की।

जब हम पाकिस्तान बस में जाने के लिए तैयारी करते हैं, मेरा कहना है कि उनसे जरूर रिश्ते रखिए, लेकिन मेरे गांव में जो अब्दुल्ला रहता है उससे भी अच्छे रिश्ते बनाने की तैयारी हमें रखनी चाहिए। इसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी कुछ कहा गया है।

I quote:

"There is a great need to sensitise the Government machinery at both Central and State levels. I must emphasise here that no tangible progress will be made unless the officers and employees concerned adopt a proper approach to involve the people in the implementation of these schemes."

मुझे लगता है कि इस देश की नौकरशाही के बारे में अलग तरह से सोचने की आवश्यकता है। नौकरशाही सही नेतृत्व के हाथ में हो तो अच्छा काम कर सकती है। मैंने खुद १७-१८ साल इनके साथ काम किया है। जिस राज्य से मैं आता हूँ, वहां ब्यूरोक्रेसी का अच्छा नाम था, हो सकता है पिछले दो-तीन साल में वहां कुछ खामी आई हो। लेकिन भारत की ब्यूरोक्रेसी की दुनिया में इज्जत है। अगर कुछ कमी है तो उसका दोष हम उनको नहीं दे सकते। जैसे एक अकुशल कारीगर सारा दोष औजारों पर देता है इसलिए केवल उन्हीं पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। जब काम करने वाले सरकार के कर्मचारी हैं, उनको सुविधा मिले, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मगर आज के समय में जो केन्द्र में सरकार है, हम देख रहे हैं कि उसके शासन में कभी डाक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं, कभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, कभी कृषि वैज्ञानिक हड़ताल पर जाते हैं और कभी एन.टी.पी.सी. या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे परिस्थिति दिन-ब-दिन खराब हो रही है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब एम्स के बारे में दिल्ली के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया जिसमें वहां के वैज्ञानिकों के लिए अलग तनखाह देने की सलाह दी गई, मेरा अनुरोध है कि सरकार इसे स्वीकार करे और आगे अपील न करे। जब मेडिकल वैज्ञानिकों को अलग तनखाह देनी है तो उसी तरह खेती के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं या अन्य क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनको भी देने की तैयारी सरकार को रखनी चाहिए।

एक आखिरी मुद्दा मुझे रखना है। शासन के राष्ट्रीय एजेंडे के बिंदु संख्या ३५ में आम सहमति से सरकार चलाने की बात कही गई है। मैं उद्घरण देना चाहता हूँ।

"We will, therefore, strive to develop national consensus on all major issues concerning the nation by involving the opposition parties and all sections of the society in dialogue. We will also try for the consensual mode of governance as far as practicable."

मुझे खुशी है कि यह बात बड़ी अच्छी कही है। कुछ दिनों से हम बिहार की बात देखते हैं। क्या इस सरकार ने सहमति के लिए कोशिश की? इससे पहले भी अखबारों में कुछ कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों से एक और बात को लोगों के सामने रखा कि हम विश्वासघात सप्ताह करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बिहार के बारे में कुछ कदम भी उन्होंने उठाए हैं। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बिहार के बारे में सरकार ने जो कदम उठाया, क्या इस बारे में आपने मेजर अपोजीशन के साथ या उनके साथियों के साथ कभी एक दिन भी बातचीत की? आपने निर्णय दिया और आप चाहते हैं कि आपके निर्णय में हम सहभागी हों? आप यहां दलितों की बात करते हैं, दलितों की हत्याएं वहां हुईं, इसका कोई स्वागत नहीं करेगा लेकिन हत्या करने वाली कौन सी शक्ति है, यह सारी दुनिया जानती है। रणबीर सेना को किसका समर्थन प्राप्त है, यह सारी दुनिया जानती है। रणबीर सेना को किसकी मदद मिलती है, यह सब जानते हैं। रणबीर सेना ने दलितों की हत्या करने के बाद बिहार सरकार को वहां से उखाड़ फेंका, इसको कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। दलितों की जो हत्याएं हुईं, इसके लिए वहां राबड़ी देवी सरकार की जिम्मेदारी थी। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और इसलिए हमने अपनी नाराजगी भी पब्लिकली ज़ाहिर की। इस बारे में हम कभी कमप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि उन्होंने कहा कि हमारा विश्वासघात हुआ है और हम विश्वासघात सप्ताह करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सहमति से सरकार चलाने की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष और बाकी साथियों के साथ बातचीत करने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The allies will not allow.

SHRI SHARAD PAWAR : That is also a problem.

हम मांग कर रहे हैं कि आप विपक्ष से कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने से पहले बातचीत कीजिए और इससे पहले आप अपने साथियों से बातचीत कीजिए। इसमें भी यूनेनिमिटी नहीं है। बहुत से मुद्दों पर हम देखते हैं कि संसद में विरोध होता है। उनकी मुश्किलों को हम समझते हैं, वे अपने साथियों के साथ बातचीत नहीं कर सकते तो सहमति की राजनीति देश में कैसे करेंगे? इस पर जो उन्होंने कहा कि विश्वास रखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सिर्फ एक-दो मुद्दे जो यहां उठाए गए, खास तौर से सुषमा स्वराज जी ने जब भ्रष्टाचार की बात पर यहां बड़ी गंभीरता से कहा। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने यह कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में सरकार पर आरोप करने के बाद यदि उस आरोप का कोई आधार नहीं हो तो कितनी मानसिक पीड़ा होती है। मुझे खुशी हुई कि उन्हें इस बात का अंदाजा तो हुआ। मुझे याद है इंदिरा गांधी जी पर नजरवाला केस के नाम पर इस सदन में कितने दिनों तक बहुस हुई थी। कितने दिनों तक उनके ऊपर हमला हुआ था। पुराना रिकार्ड निकालिए, पता चल जाएगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? बोफोर्स के बारे में पिछले नौ-दस सालों से इस सदन में ५५ घंटे और १७ मिनट बहस हुई। पिछले साल तक इस बारे में बहस हुई। बार-बार यह मुद्दा लिया गया। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद आज यह तीसरी सरकार आई है। एक साल अभी इस सरकार को पूरा हुआ है लेकिन आज तक बोफोर्स के बारे में, राजीव गांधी जी को पीड़ा देने का काम इन्होंने किया। इस बारे में किसकी जिम्मेदारी थी, यह साबित करने में वे कामयाब नहीं हुए, यह वस्तुस्थिति है। यह बात हमने कई बार कही है। इस तरह से आरोप लगाना ठीक नहीं है। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे जब एनरॉन का प्रोजेक्ट क्लियर हुआ था मगर पूरे देश ने देखा कि आरोप करने वाले लोगों ने ही बाद में एनरॉन को मान्यता दे दी और केवल मान्यता ही नहीं दी, बल्कि बड़े पैमाने पर मान्यता दी और तब ५०० मेगावाट की जगह २४०० मेगावाट को मान्यता देने का काम इस सरकार ने किया।

समुद्र में एनरॉन को डुबाने वाले लोगों ने आज २४०० मेगावाट का प्रोजेक्ट फिर से क्रियेट किया। पावर लाने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं तो हम उनके खिलाफ नहीं हैं, मगर जिनकी जिन्दगी आरोप लगाने में गई आज वे हमें सलाह दे रहे हैं, इससे मानसिक तनाव पैदा होता है और बड़ा नुकसान होता है। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आज जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है, जो देश की आर्थिक स्थिति है, दुनिया में एक अकेलापन भारत में हम देख रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है इससे हमें देश को बाहर निकालना होगा। जब देश को बाहर निकालना होगा तो सेक्यूलरिज़्म के इशूज़ पर जब तक सफाई न हो, स्पष्टता न हो तो वह देश को कभी आगे नहीं ले जा सकता। इतना ही कह कर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ।

#### TEXT OF AMENDMENTS

[FOR THE TEXT OF AMENDMENTS TO THE MOTION OF THANKS  
ON THE PRESIDENT'S ADDRESS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT  
PAGES 5968 - 5984]

SHRI C. SREENIVASAN (DINDIGUL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, On behalf of the AIADMK, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address.

At the outset, I welcome the positive steps taken by the Prime Minister and the Government in smoothening the relation between India and Pakistan. The bus to Lahore is really a new bridge in relations between the two countries. Such exchanges should be encouraged.

I would like to congratulate the Government for demonstrating to the outside world our nuclear capabilities. The Government should not come under any compulsion to sign the CTBT. National interests should be given top priority while dealing with such issues.

As far as defence of the country is concerned, we are still heavily dependent on foreign suppliers in key areas. Self-reliance in defence has to be achieved.

I welcome the New Agricultural Policy. It should aim at introducing technological revolution in all agricultural activities. While the land should belong to the owners, cultivation methods and choice of crops should be jointly decided by owners as well as by the Government after assessing the market and commercial forces in operation. This would ensure profits for the farmers as well as yield for the society.

The Cauvery river water dispute is yet to be solved in favour of Tamil Nadu farmers. The Government should implement the interim Award of the Cauvery Tribunal so that Tamil Nadu farmers are fully protected as demanded by my leader.

I also welcome the Free Trade Agreement reached between India and Sri Lanka in December last year. However, the problem of Indian fishermen being fired at by Sri Lankan navy still remains unresolved. The interests of Indian fishermen in Indian seas should be protected at all costs. I want this Government to initiate a special dialogue with the Sri Lankan Government on this matter.

Two days back, Parliament has adopted a resolution in support of women reservation. As far as the representation of women in Parliament and State Legislatures is concerned, the AIADMK is totally in favour of enactment of the Constitution Amendment Bill at the earliest.

I also welcome the New Policy for supporting older persons. These social measures will go a long way in developing a decent and civilized society.

I convey my thanks on behalf of my leader, Puratchi Thalaivi, Dr.J.Jayalalitha to the Prime Minister for allocating funds for executing the Sethu Samudram Project at the request of my leader. I hope the august House

would continue to extend its support to the hon. Prime Minister, Shri Vajpayee for serving the nation more and better.

With these words, I once again support the Motion of Thanks on behalf of the AIADMK.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Deputy Speaker, Sir, it is a matter of regret that our respected Rashtrapati Ji was required to indulge in inanities in the form of an Address which he delivered to the Members of Parliament assembled together from both the Houses of Parliament. This Address was prepared by a political aberration which somehow has assumed power to the great detriment of this country and the common people. Of course, it is for a very very temporary period. Its only merit, if at all there is any, is in its length and not in its depth or in its contents. It is full of... (Interruptions) Why are you laughing? Maybe, you do not know what your fate is.... (Interruptions)

I am sure, Sir, you must have gone through this document. I am sure you will fully agree with me that this contains only vague, demagogic generalisation and pious platitudes. Sir, today, in the hands of this Government, I find a very important occasion, namely the Address by the President to the Members of Parliament, has just become a ritual, a formality. What is the purpose of this Address? What for did the founding fathers of our Constitution provide this occasion? This is supposed to lay down the direction which the country should take in the coming years. It should also contain a proper assessment of the performance of the Government. It should also highlight as to how the main issues confronting the people will be resolved. Of course, it is not expected to contain details for which the Budget, policy declaration and formulation will be there. I was not surprised that this Address did not contain anything like that. It does not meet the requirement of an Address to both the Houses of Parliament.

Can anybody deny that the hon. Finance Minister is being lauded in the common people? Every day, in TV news we are being told about the points that the share exchange index has reached, as if that is the only criteria! What is the fate of the common people? How many job opportunities are being created? I am happy that the Finance Minister finds himself a lot of amusement in what I am saying. But the last laughter will not be by him but by the common people of this country... (Interruptions) We have seen what happened in Delhi where the venerable Prime Minister was made to address almost street corner meetings.

The result is that Shrimati Sushma Swaraj is here. Now, she does not know what to do except to quietly sit here. Where is Shri Khurana? What has happened in Rajasthan where they were supposed to be so strong. They could best find it out through the ballot boxes. Do they have respect for the democracy and the wishes of the people?

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर): आपको दिल्ली में क्या मिला?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमारी छोड़ो। अपनी बात सुनो। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता।

... (व्यवधान)

Sir, this is the difficulty. Shrimati Sushma Swaraj always exploits my great esteem and affection for her. I do not know how such an intelligent and articulate person is sitting there. Even the constituency which she naturally won with her grace and charm, was lost forthwith by her party in the by-elections that were held as soon as she resigned. Have you any respect for the people's verdict? Are you not seeing the writing on the wall? Why is it happened? They said with a great gusto about 'able Prime Minister and stable Government' But his 'only ability is to have the stability of the Government' But how did it happen? Ability is not in governance. Ability is again the stability and the stability is unpampering your allies.

I said the other day that Shri Atal Bihari Vajpayee has ceased to be concerned with the tears of the common people in this country which he promised to wipe out. Now, he is more concerned with the frowns and the smiles of his allies. Today this country is being decided how to keep them pleased one after another. So many demands are coming and packages after packages are being given. Can any country be governed by the packages of allies? All sorts of promises are being made. Ministers are being sent to different State Capital to satisfy their allies. They are making all sorts of promises. It is for the allies to believe all those promises. We are soon going to -- I do not know if it is our misfortune -observe the anniversary of their coming to power. Let us see what has been done. We have seen what has happened in Tamil Nadu where lawyers are changed, judges are changed and



Special Courts are changed. Let us see if one of these decisions and actions is for the benefit of the common people. Kindly test it.

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : यह क्या बात है ?

... (व्यवधान)

ऑटोग्राफी लिखने वालों को वाईस-चांसलर बना दिया।

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां बदला ले रहे हो।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Chetan Chauhan, no running commentary please.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, all the promises which have either been made in the National Agenda for Governance or adverted to in the Address of hon. Rashtrapatiiji have shown to be totally unfulfilled and which cannot be done by them. Today, the people are groaning under the miseries... (Interruptions). Sir, what is happening here? Has this House stopped to be a place for discussion and debate? Are we depending on some hon. Members' wishes and ipse dixit? If so, let us be told; we will go out.

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): जब इधर से कोई बोलता है तो क्या यह टोका-टाकी नहीं करते हैं ? इन्हें इस समय सारी कनवेंशन्स याद आती हैं।

... (व्यवधान)

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I appeal to all hon. Members not to indulge in running commentary from any side? Otherwise, I will have to take them to serious task.

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Mr. Deputy-Speaker Sir, I have great affection and respect for them. I respect all of you. Please have a little patience. You can demolish by your articulation.

I was saying that common people of this country are groaning under severest burden which has been imposed by this Government because of price rise, because of what they have done to PDS and new imposts have been levied even before the Budget has been announced. It is becoming impossible for the common people to bear them. But there is not a single word mentioned here as to how to alleviate their sufferings.

Over and above that, what concerns the people of the country the most is the attack on the unity and integrity of the country. It has never been under such severe strain as it is today. Recently, we have seen a deliberate attack also on the federal and democratic set-up of this country. We have never seen such political insincerity, to put it very mildly. It was in the shape of imposition of President's rule in Bihar, knowing very well that they cannot have it approved by the Rajya Sabha. As the Leader of Opposition asked just now, what is the method of governance they have thought of? Did they consult the Opposition without whose support they cannot pass it? He openly said just now on the floor of the House they they were not consulted. Now, do they have any obligation to support you just because you happened to take the most undemocratic and anti-federal decision in this country. What has happened to this party? I do not know. Therefore, power for one year has totally unmassed this political party. We had thought that they had some commitments to some basic principles like federalism and their opposition to Article 356. At least, they had been fighting for that throughout on the floor of this House. I had seen it and I had the occasion to walk with many of my distinguished friends on the other side

in this very House. As I said, Shri Vajpayee and Shri Advani walked with us to Rashtrapati Bhawan in protest against use of Article 356 against NTR. Now what has happened has totally unmased this party. Only skin deep attachment or commitment to parliamentary democracy and federalism is there so far as this political party is concerned.

In the recent memory, we have never seen what we have seen during the regime of this Government - the calculated onslaught, physical attacks on the minorities in this country. Sir, not one word has been said in the President's Address on this point. Not one word has been said about the cries of those people who have been beaten up, whose places of worship had been demolished and whose religious books have been burnt. Shall we decide, our citizens, on the basis of the Gods they worship? Shall we decide and differentiate between man and man because of that? Secularism is the basic feature of our Constitution. There is some reference to it somewhere which I find in this book. Is this the way we are paying respect to that most basic feature of our Constitution? Federalism and parliamentary democracy have been held by the Supreme Court of India as the basic features of our Constitution. Today, all these basic features lie in shambles in the hands of this Government and Sir, I am very sorry to say that Rashtrapatiiji, because of his Constitutional obligation, had to read out an address which is an insult to the common and suffering people of this country.

I do not find Shri Madan Lal Khurana here. Why was he not allowed to make a statement which he wanted to make? His resignation shows that there is something. He referred to one thing. That is what we saw in the newspapers. He is a gagged person. He cannot speak. A Member of Parliament cannot speak! He referred to the attacks on the Christian minorities and the dubious role played by his previous mentor the RSS, the Sangh Pariwar which is now controlling this Government. He has said this. He was a very distinguished Member of this Government. Shrimati Sushma Swaraj, I think he has not yet been expelled from the Party! He may be on the verge of it. I do not know about it.

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली): क्यों हमारी चिन्ता करके कमज़ोर हो रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम तो चिन्ता करेंगे।

Unfortunately, you are in power.

आपकी चिन्ता करनी पड़ती है हमको।

Mr. Deputy-Speaker, Sir, have you got a copy of the President's Address?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Kindly see page 1, paragraph 3 which says like this.

I quote:

ऑनरेबल राष्ट्रपति जी के मुंह में बैठा दिया।

"I am happy to note that the National Agenda for Governance, which is the common policy covenant of the coalition Government, is being implemented faithfully."

Unfortunately, it is not within the inverted commas! I quote further.

"In the past eleven months, my Government has acted decisively on many fronts to promote people's welfare, accelerate economic development, strengthen internal and external security, and develop deeper bonds of friendship and cooperation with India's neighbours and other countries. Taken together, these initiatives have instilled a new sense of self-confidence among Indians, increasing our ability to effectively face the challenges of the present and the future."

Yes, people have shown self-confidence because they have already expressed their view that they would get rid of this Government as soon as they get an opportunity...(Interruptions) But let us see whether this National Agenda is implemented faithfully.

Let us start with women. Let us see in which page it is there. Kindly see the heading "Empowerment of Women". Shrimati Sushma Swaraj, have you got a copy of it or have you thrown it into the waste paper basket?  
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : Shall I show it to you?  
SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You have got a copy of it. All right.

आप बोलती हैं तो ठीक है।

Is it an amended version?... (Interruptions) It has been stated and I quote:

"We will legislate for the reservation of 33 per cent of the seats in Parliament and the State Assemblies for women and also institute plans for providing free education for girls up to the college level including professional courses so as to better empower women. We will also set up a Development Bank for women entrepreneurs in the small and tiny sectors."

Please tell us what you have done. How much is implemented?... (Interruptions) What does the present President's Address say in paragraph 39? I quote:

"The Government has launched the Rural Women's Development and Empowerment Project in six States. A National Policy for Empowerment of Women is finalised. A new initiative in child development would be the setting up of a National Commission for Children."

Which one has been implemented at all faithfully?

About education, you take any one item. Take, for example, Eradication of Unemployment. It is a burning issue in this country. From the National Agenda, we find this: recognising the right to work of every citizen. There, it has been stated:

"The main thrust of the new Government will be Berozgari Hatao."

If one does not understand it in English, they have to translate it as "eradicate unemployment." It has been further stated:

"As against the present trend of jobless growth, our Government will measure growth by generation of gainful employment."

Let us see what has been said here and how it is faithfully implemented. Only one sentence is here. I will show it to you. It is being implemented by the closure of the Public Sector Units and creating more unemployment. It is trying to force upon them VRS.

Now, what is the state of the faithful implementation of this? I quote paragraph 12 of the Address:

"The National Agenda for Governance calls for an accelerated and well-balanced economic development as a precondition for fulfilling the goal of Berozgari Hatao. The Government has set the target of an annual GDP growth rate of 6.5 per cent."

At the end of it, nothing. I do not know. I am sorry. I was in some other meeting. I wanted to listen to our distinguished Member Sushmaji. How did you support this? You should get a Param Vir Chakra. Take any aspect. For example, all these talk about friendly relations in the international arena. What is the situation today? Who is our friend? We have commended; we appreciate the efforts of the hon. Prime Minister. After queering the pitch, making ourselves friendless in the whole world, he has taken this bus ride. We have supported it. Any attempt is good. But what benefit this country has obtained? They thought that there will be such euphoria in this country that they would not have to bother for anything after the blasts.

Till today eight-nine rounds of talks have been held by our distinguished Foreign Minister with somebody at the Joint Secretary and Under Secretary level. They met eight times. I am very sorry because I have personal respect for Shri Jaswant Singh and also for Shri Yashwant Sinha. All Jaswants are good. In bad places though, however. What is happening? It is an unseemly sight.

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : सोमनाथ भी अच्छे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारी पूजा करने से कुछ नहीं होगा।

Advaniji started his Rath Yatra after praying not to me but he had pooja at the Somnath temple. At least do not interrupt me.

Today what has happened? Yes, we are supporting it. We want closest friendly relations with Pakistan and Bangladesh; with our neighbours; and with every country in the world. Is that the position today? With great bravado you make allegations against China. What is the position today with every country? position.

Sir, with regard to the defence services - I am not going into the details - such an important event as a dismissal of a Naval Chief has taken place. They should have mentioned it. What can our Respected Rashtrapati do? He has obliged to read it out only as it is printed. I hope it was better printed there. Not one word is there. Is it a matter of total insignificance? We shall have the occasion to go through it. I hope the Congress presses for the JPC.

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): Yes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Do not be carried away like the patents.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM (GARHWAL): Private commitment is being taken in the Lok Sabha.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): In the presence of Mr. Speaker, Mr. Deputy-Speaker and in the presence of all your friends.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am helplessly watching.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : So far as this is concerned, everybody has said that it is an unprecedented event. Now, the hon. Defence Minister felt that this House is not a proper place to make his views known. He goes to the press and says that it is 'civilian control' and ultimately has ended up with 'security risk'. In between so many conflicting statements, the hon. Prime Minister goes to Andaman and there he thinks of this issue.

The Session has started on the 22nd of February. Until we raised it here, they did not bother and when they found that they have to face it, they want to explain it only in a Committee meeting. Is this a routine matter?

Sir, we are all proud of our defence forces. Fortunately they have remained unpolluted by politics of any kind so far. I sincerely hope that they would remain unpolluted inspite of their well-designed intention to penetrate everywhere on the basis of religion. I hope, they remain immune from this attempt. But a calculated attack is now being made and today, one Defence Chief has gone, another Defence Chief goes to the Press and makes a statement, so many Ex-Defence Chiefs are issuing statements. What remains of this country?

Sir, so far as the economic situation is concerned, apart from the price level, apart from the lack of job opportunities being created, where is the growth? I have never seen such an inconsequential and useless document such as the National Agenda for Governance. It says:

"We will bring GDP to 7 to 8 per cent bracket and control deficits, fiscal and revenue."

What is the percentage now? It is 3.5 per cent. I hope the Finance Minister does not get another opportunity to present the Budget. Then, when will they do it? They never said that they would achieve this target at the end of the five year term.

MAJOR GENERAL BHUVAN CHANDRA KHANDURI, AVSM : There are four more years.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : You make your own calculations in your office.

Sir, the President's Address says that the Government has set the target. The hon. Rashtrapati is asked to say that the Government has set the target of an annual GDP growth rate of 6.5 per cent. It has come down from 7 to 8 per cent which they have mentioned in their National Agenda for Governance. But it is only 3.5 per cent now.... (Interruptions) Sir, the Finance Minister does not agree with me. I make it 4 per cent. I am more charitable to him; I make it 4 per cent.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Please read the Economic Survey.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : He says it is 5.8 per cent. Have we reached it? I was trying to find out as to how do we reach that target. Is it by mere words? Let them tell us what is their direction either in their Budget or in the President's Address. How are they going to do it?

Sir, what is going to happen to our own industries? What is the crime of being employed by the public sector undertakings of the Government of India? Are they criminals? Are they anti-nationals? As a matter of fact, it was said by them that they would try to evaluate them on a unit-to-unit basis as to whether they can be saved or not. With regard to disinvestment, I find that Shri Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram are being beaten hollow by Shri Yashwant Sinha. They say that the Disinvestment Commission must be given effect to and they want to collect Rs.10,000 crore out of disinvestment. I am no economist, nor an expert, nor a juggler. But what has happened by the swapping of the Government shares? They have realised Rs.3,500 crore. It is nothing but a financial jugglery. Is this the way to raise revenue to meet their Budget deficits?

Sir, it is not a question of opposition for the sake of opposition. These are issues which are troubling the people everyday. In every sphere of today's national life, these problems are there and we do not know how they are



going to be solved. This Government cannot solve them.

The other point to which I have to come back once more is the question of misuse of article 356. Kindly see how this was done. From the time of election, they had promised to impose President's Rule in Bihar if they came to power. Can it be a matter of election manifesto of any responsible political party or can it be an election issue of any responsible political party who has any attachment to the principles of Constitution, principles of federalism. It was trying to please its allies saying, "if I come to power there, I shall utilise article 356 of the Constitution in dismissing the Government"?

They have got 25 per cent of the popular support. They cannot form a Government on their own. They have taken help of their allies. I do not blame them. It is for them to commit hara-kiri or not to commit hara-kiri by joining them. They have joined them. Now, because of arithmetic of numbers, they have formed the Government thanks to Shri K. Yerranaidu's last minute decision.

If the cellular telephone does not operate, I do not know what will happen. Or if the STD does not operate, we do not know what will happen. With their good wishes and blessings, this Government was saved on that day and even on this day.

We know very well that the Telugu Desam in Andhra Pradesh has always opposed article 356. BJP has opposed article 356. All their parties have opposed article 356 because, at one time or the other, they have been victims of this. Now, when they tried to impose the President's Rule earlier. Rashtrapatiiji returned that. After five months, that report is submitted again on the basis of article 74 of the Constitution telling the Rashtrapatiiji : "You are bound to approve of this because it is resubmitted after reconsideration." And that signature is detained knowing that, they have not got the support of both the Houses in this Parliament.

I have never seen it in my humble experience in this House. I have seen so many Presidential Proclamations have been brought before this House. But with such cavalier attitude, with certainty of being defeated and with as I said the other day - such gusto and bravado. They said that they got the support of the people which has been proved by the House of the People voting in favour, then, what more do you want? Then, this attempted dinner diplomacy. It did not succeed. Is this the way the country should be run? Can you just dismiss the State Governments which have been elected? I said it the other day. Shri L.K. Advani said, "People's support is there." How do you ascertain the people's support in a parliamentary democracy? Is it through opinion polls or going to the people to get their verdict? When is the next election?

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अगले साल होंगे।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Within one year, the election is to be held. The people will give their verdict. Now, you send your RSS functionary as a Governor there. The Sarkaria Commission repeatedly said, "Do not appoint any political person." In any event, no Government should appoint somebody who belongs to its own party. Knowing that, they sent him. Now, the President's Rule is applied. A person like Shri L.K. Advani, one of the seniormost leaders of the BJP - the main ruling party - says, "We should change him."

We want apolitical person. Then, Sir, what happened? The respected Governor came back with his bag and baggage in Rajdhani Express, which was very well advertised. He did not use the Government car. He did not utilise the hospitality of the Government. He stayed in his follower's house. Then, Sir, our Home Minister prostrated before him and gave a statement in writing that he is sorry, he may be excused; otherwise he will lose his job. Then, the Governor went back with bravado in his official plane. This was the tamasha which took place on in this country.

I saw the gentleman whom I am referring to on TV so many times saying that he was proud to be an RSS person. Is this way to run the country? Can we maintain the unity and integrity of this country? Are not the respective State Governments elected with the support of the people? Can we just play with them? After the President's rule was imposed, within a short time, there were killings. Did the Government dismiss the Governor? This is the pernicious thing which is being taken recourse to. The founding fathers have said that this most draconian provision should not be taken recourse to except in the rarest of rare occasions. It is being glibly taken recourse to and then they ask somebody else to support it. If you do not support it, then the neo-convert will say "Well, well, it shows the anti-dalit character of the Congress". They nurtured him and brought him here. Where is he? Where is my nephew, Shri Kumaramangalam? Of course, I have said that he had been faithfully

following all the bad habits, decisions and wrong policies of the Congress Government but now he is following them in a much less articulate manner. They were pucca rulers for 45 years. You are kutcha rulers.

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): क्या कह रहे हैं आप ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि सुनाई नहीं दे रहा है तो ईयरफोन लगा लीजिए।

Sir, this is the tragedy of this country. When you have to make efforts to unite the country to meet the challenges of poverty, unemployment, lack of progress, and attacks from multinationals, this country is being divided on the basis of religion, on the basis of politics. Therefore, this Address is nothing but an insult to the people of this country. It is nothing but a mockery which is being played on the people of this country. They make all sorts of flimsy promises; they make all sorts of references to the National Agenda for Governance but they failed miserably in every sector.

Now, I would like to know from the hon. Prime Minister how this Government is being run. There was a declaration by the Industry Minister that eight public sector undertakings will be closed down. The Finance Minister might have given his blessings to that. Members of Parliament from West Bengal, irrespective of the political affiliations were representing to him not to do it. If it is done, then thousands and thousands of workers will be on the street for no fault of theirs. They have requested him to do something to revive those undertakings. The Chief Minister of West Bengal repeatedly requested him to do the needful. He had met him also but no action was taken, not even a response came from him. So, we are not at all taken care of. But when an ally makes a request or demand, immediately, special meeting is called, photographs are published and so on. Recently, as there was a request from one of their allies, they have decided to keep the matter in abeyance for three months.

Is this the way to run the country? Is it their political bonafide? The whole attempt of this Government is somehow to remain in power, as I said earlier.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): Sir, it is 6 o'clock. The time of the House has to be extended.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has been extended. It was decided earlier.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I know this is happening. The Minister for Parliamentary Affairs does not know that the time has been extended... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It was decided that it has been extended up to 8 o'clock.

SHRI RAM NAIK: I would like to know when it was decided.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It was decided in the morning.

SHRI RAM NAIK: When it has been extended?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, after Question Hour it was decided.

SHRI RAM NAIK: But Sir, the sense of the House has to be taken. Whatever is decided in the BAC has to be conveyed here. The senior leader of this House, who has been given the best parliamentary award should know that the sense of the House has to be taken... (Interruptions) I would request him not to throw on me whatever he wants to say... (Interruptions) This is not the way. He is a senior Member. He must know that the sense of the House is to be taken ... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I withdraw... (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: Yes, that is good... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, yesterday also we had taken a decision.

SHRI RAM NAIK: Sir, my point is that it is always done and if the procedure is followed, I have nothing to say.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, what has been decided and announced here is considered to be taking the sense of the House. Yesterday also the same thing happened.

... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR (BARAMATI): Mr. Deputy-Speaker Sir, if the hon. Minister has got some objection, then we will sit tomorrow because it is already 6 o'clock... (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: I have not objected. The hon. Member has not understood me. What I said was that the time of the House had to be extended and that it was my duty as the Minister of State for Parliamentary Affairs to

draw the attention of the House. That is what I had done. I have not objected. I think, I am misunderstood...

(Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : We have understood everything. You wanted to obstruct him only... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, is it the sense of the House to sit up to 8 o'clock?

SOME HON. MEMBERS: No.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes. So, the House is extended up to 8 o'clock.

... (Interruptions)

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I have withdrawn my comments in deference to his intervention, but I will check up whether it has been already extended or not... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : So, we will sit tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please.

SHRI SHARAD PAWAR : Sir, there is no unanimity. We will sit tomorrow... (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: But I have not opposed to this... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : But there is no unanimity in the House... (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: Shri Somnath Chatterjee has understood me... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I appeal to the hon. Members?

... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : No, Sir, he has objected to a senior Member ... (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: I have not objected ... (Interruptions) I have just appealed ... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : Sir, we have reservations. There is no unanimity, so, we will sit tomorrow...

(Interruptions)

SHRI RAM NAIK: But Shri Somnath Chatterjee has agreed... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : No, he will speak tomorrow... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : But Sir, let me finish my speech... (Interruptions) May I finish, Sir? Let it be extended till 6.30 p.m. I will conclude by this time... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : All right. We will sit till he finishes his speech... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I will finish it in five minutes... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I inform the House that even in the Business Advisory Committee we had taken a decision in this regard, that is why I just reminded the House in the afternoon, at 12 or 1 o'clock, that the House was going to set up to 8 o'clock from today. There was an announcement from the Chair.

... (Interruptions)

SOME HON. MEMBERS: No, Sir, we do not agree to this... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : No, Sir, we have heard that if a senior Member like Shri Somnath Chatterjee has to take a lesson from the Minister of State for Parliamentary Affairs then we want some time for that. So, we will sit tomorrow... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, please.

SHRI RAM NAIK: Let me not be misunderstood... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please.

... (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I only drew your attention to the time. I did not say anything. ... (Interruptions) I only drew the attention of the Deputy-Speaker to the time. That is my duty. As the Leader of the Opposition, you must help us. It is my duty to draw the attention of the Deputy-Speaker that the time is coming on. That is what I have done. ... (Interruptions)

SHRI SHARAD PAWAR : Sir, it is also my duty to protect the respect and prestige of a senior Member like him. ... (Interruptions)

SHRI V. SATHIAMOORTHY (RAMANATHAPURAM): Sir, the contention of the Leader of the Opposition is not acceptable. It is the duty of the Parliamentary Affairs Minister to draw the attention of the Chair as to whether the time of the House is extended or not. ... (Interruptions) Mere reminding the time to the Speaker will not affect the prestige of any member. Whether Senior Member or Junior Member, everyone is equal before the prestige of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you please resume your seat?

... (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, tomorrow I am in difficulty. ... (Interruptions) There are two more issues. I shall mention them briefly. One is what was being said in the national agenda about corruption. This is a very important issue and became a live issue. I quote paragraph 24, which says:

"We will enact a Lok Pal Bill with adequate powers to deal with corruption charges against anyone including the Prime Minister. In the administration of justice, we shall not allow discrimination between the rich and the poor, the empowered and the powerless, restore the majesty of law and the objectivity of the State."

Sir, what has happened to the Lok Pal Bill? The Government has to tell about this Bill. On the other hand, we find newer and newer charges of corruption against this Government. As a matter of fact, some of them have already been raised. Serious charges of corruption have been made now but not a single action is being taken and they want to avoid discussion even on the floor of the House until today, Sir, something has happened; very grudgingly they have agreed to have a discussion.

Sir, we would like to know what is the action taken by this Government to fight against corruption. What has happened to the Lok Pal Bill?

Now, I quote paragraph 21 of the national agenda:

"We are convinced that there is a clear case for devolution of more financial and administrative powers and functions to the States. We will take suitable steps to ensure harmonious Centre-State relations in the light of recommendations of the Sarkaria Commission and effect decentralisation right up to the grassroot level by activating, involving Panchayats and local bodies."

Sir, nothing has happened. On the other hand, Sir, a deliberate attack is being made on the proper Centre-State relations. Therefore, Sir, the electoral reforms is only about State funding. A Committee was formed under the Chairmanship of comrade Indrajit Gupta. We have had the privilege of being its members. We have submitted a report. I do not know when that would be brought. The Bill has not been even circulated. We do not know as to the decision that the Government will take on electoral reforms, on which we have been listening from Shri Atal Bihari Vajpayee and Shri Lal Krishna Advani for years. Where is the electoral reform legislation? Where is it? There is not even one word about that in the President's Address also.

Sir, now what has happened to Prasar Bharati? Shrimati Sushmaji, I do not know whether it is one of the reasons you have been shunted out.

Prasar Bharati has become today the matter of personal control of the hon. Minister. He says Doordarshan cannot have two policies. Prasar Bharati is not being allowed to function. I saw in the papers that the Members of the Board are meeting the Prime Minister. The Chairman is not there. The other Members are not fully there. They are not being allowed to act. In the meantime, we are seeing the grossest misuse of the electronic media. As a whole, it has become an extension, not of the Government, but it has become an extension of the publicity machinery of BJP, of course, minus some of the leaders like Shrimati Sushma Swaraj. She is no longer seen. Those who are outside their favourite circle, they are out. Now, it has become their publicity wing. You will have to see that the allies are given time on the basis of their own survival. Then, what commitment is there of this Government? Which clause of the national agenda they have implemented in this one year? Which is the thrust of the Address?

As I said, the hon. Finance Minister will receive kudos from a very minority section of the people in this country who has got all the things in this world, but not by the common people. They are not thanking them. I do not know how many telegrams he has received from the common people, hutment dwellers and unemployed people for the "excellent Budget" that you have delivered.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I submit that this country's future can be protected by getting rid of this aberration and this motley combination masquerading as Government of India. When we are going to enter into the new millennium, this country needs proper approach, proper outlook and a proper dedication. It is a dedication to the maintenance of unity and integrity of this country. Nothing can be more important. This country needs a dedication to the basic features of this Constitution; federalism, parliamentary democracy and secularism. Each one of which is being trampled down by this Government for their own political ends. Therefore, it is our duty, duty of all the right thinking people of this country. I am sure they have already expressed, as we know, their verdict against this Government in three important States of this country. It is high time that this House expresses itself in a manner which will show that the misgovernance cannot be allowed to continue and it will come to an end. Therefore, I am sorry I cannot support the Motion and I oppose the Motion with full vigour. I am sure some of the people there are my good friends, very hon. friends with great patriotism but they are following misguided policies and programmes which is tearing this country apart. Therefore, our obligation is to get rid of them as soon as we can. This will be for the good of the country.

(ends)

SHRI SHARAD PAWAR : Let us adjourn it for tomorrow.

SOME HON. MEMBERS: Tomorrow.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Will you kindly resume your seats? Please resume your seats.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : जिस ढंग से बात हुई, वह बराबर नहीं हुई।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly resume your seats. I have to say a few words. Will you please sit down? I would appeal to hon. Members. We are very short of time.

SHRI DATTA MEGHE : We are sitting on Saturday.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Business Advisory Committee had taken the decision. It has already been circulated also. We are sitting up to eight o'clock. Please cooperate.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : If it was circulated, then the hon. Minister was not right. I was right. But he abused me. He abused me on the floor of the House. when I was speaking. You were not here.

Please admit it Mr. Minister. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wait. I am on my legs.

The Business Advisory Committee Report was submitted to the House.

SHRI MOHAN SINGH (DEORIA): But the Minister was saying something else.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mohan Singh, a mistake can be committed. What is there? He has already expressed his views.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : It was on the assumption that he was right. SHRI SHARAD PAWAR : If the decision was already circulated, then where was the necessity for the hon. Minister to mention it? Were was the need to obstruct the hon. Member when the decision was already taken? (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): The Minister has behaved in a manner unbecoming of a Minister.

SHRI RAM NAIK: Let me clarify. (Interruptions)

SHRI RUPCHAND PAL : It was unbecoming of a Minister.

SHRI RAM NAIK: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I drew your attention.

SHRI RUPCHAND PAL : It was the hon. Minister who created such a situation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has already expressed his views. He has gone back.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me complete. Do you not want me also to speak in this House?

SHRI V.V. RAGHAVAN (TRICHUR): We are not for extension. It has to be decided every day at six o'clock. You have asked for extension. We are not for extension. If it has to be decided every day by taking the sense of the House, we are against extending the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Raghavan, the House is supreme, I agree. The Business Advisory Committee consists of all parties.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: They have decided in the BAC. It was also circulated in the form of the Bulletin. Yes, there was a mistake. What happened? Anybody can commit a mistake.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not crucify him for that.

Now let us hear Shri Yashwant Sinha.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : Sir, I have been watching the proceedings as quietly as possible. The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs, to the best of my understanding, did not want the House to commit an irregularity in not extending it formally beyond 6 o' clock. Now, because it was circulated, this was a mistaken notion. He has admitted it. In view of this, I would like to appeal to all sections of the House to please cooperate with each other....(Interruptions).

SHRI DATTA MEGHE : From tomorrow, not today. (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him complete.

... (Interruptions)



SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this is a decision which has been taken by all the senior Leaders of the House who constitute the Business Advisory Committee and it has the full consensus of the House. Now, therefore, we will not be showing any respect to that decision, if we were to hurriedly take a decision to adjourn just now. I am, therefore, appealing to all sections, to all parties to please cooperate and implement the decision which has been taken. Let us cooperate with the decision. We know that we are a little behind schedule. It will only help us to catch up with it. It has already been decided. We are all saying that let us agree to implement that decision.... (Interruptions).

SHRI SHARAD PAWAR : Mr. Deputy, Speaker, Sir, there are no two opinions about the unanimous decision of the Business Advisory Committee to sit up to a particular time. I do not want to raise any objection because I am fully aware that that decision was already circulated to all the Members. But hon. Minister of State for Parliamentary Affairs got up at 6 o'clock, though a hon. Member was speaking and he was insisting that I got time, but still he said, 'no', this is the practice and we have to take the consent of the House. Until and unless we take the consent of the House, we cannot continue like this. Then, the issue was raised. The House said that there is no unanimity and there is no consent. If this objection was not raised by the Minister of Parliamentary Affairs, probably, there would not have been any problem. He has raised the problem, since the House has not accepted it and there is no unanimity, we will meet tomorrow. (Interruptions).

SHRI RAM NAIK : Sir, if the hon. Leader of Opposition does not want the House to continue, well, he is within his rights. But yesterday also at 7 o'clock when the House was extended and it was to work up to 8 o'clock, the Members said that they do not want to work. That is why, the House was adjourned. So, I thought it is proper on my part to draw your attention at 6 o'clock -- that is the practice -- even though the Business Advisory Committee takes a decision, in the House always this practice is being followed. (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him complete.

... (Interruptions)

SHRI RAM NAIK: That is why, I thought it is my duty to draw your attention and that is what I have done.... (Interruptions). Subsequently, whatever Shri Somnath Chatterjee said, he said it and I gave my comments on that. He also was satisfied at that time that this should have been done. Now, whether after circulation in the Bulletin, this type of attention is to be drawn of the Speaker or not, I feel it is to be drawn. Now, it is for you to decide whether I should do it or not....(Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anyway, I have taken a consensus. Now, the House seems not in favour of sitting.

... (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मैं मूवर ऑफ दी मोशन के नाते अपील करना चाहती हूँ जो कुछ घटा है उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ। इस बहस को आठ घंटे अलॉट किए गये हैं। यह तय किया गया है कि कल तीन बजे तक चर्चा समाप्त हो जाए। मैं नेता विपक्ष से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो कुछ बदमगजी पैदा हो गयी उसको नजरअंदाज करें और इस बहस को चलने दें, जिससे कल तीन बजे तक यह चर्चा समाप्त हो सके और सोमवार को प्रधान मंत्री जी रिप्लाइ कर सकें।

SHRI SHARAD PAWAR : Sir, you should try to understand our difficulty also. Our difficulty is that we were under the impression that after taking a decision and circulating that particular decision, there is no necessity to raise this particular issue. But the issue was raised by not less than the Parliamentary Affairs Minister. And not only that, there was some guidance also to hon. Members that they should learn this and that, though not exactly in these words but by saying that after spending 32 years in Parliamentary affairs, we should get some time to learn about rules and other things. That is why it is better to adjourn now.

SHRI RAM NAIK: Sir, if the Leader of the Opposition does not want to work beyond six o'clock, then what can we do?...(Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seats. I have to make an announcement.